I want to know when the Government of India will come to some decision about this matter and tell us plainly that they do not want to give us Statehood. I want to know from the Home Minister whether he is aware of the pitch of feelings there and very soon it will go into non-democratic methods ? Are they going to kill more young people ? I want a clear answer from the Prime Minister.

SHRI K. C. PANT : I think I have answered this question earlier. I was asked about the demand for Statehood for Telengana and I said, Government is not considering that proposal, but it is considering the other proposals to increase the economic development of the area, which to our mind is the central problem.

श्री राम गोपाल शालवाले : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड को सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया । पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये राज्य अपना खर्चा निकाल सकते हैं या फिर केन्द्रीय सरकार के ऊपर उनका कितना बोझा पड़ेगा ? परसो जब प्रधान मंत्री जी से दिल्ली का डेपुटेशन मिला था तो उस समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम देश में टुकड़े नहीं करना चाहते । मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई थी । मैं जानना चाहता हूं कि अगर वह देश के टुकड़े नहीं करना चाहती तो फिर यह छोटे छोटे राज्य क्यों बन रहे हैं ? क्या सरकार सारे भारत को पांच भागों में बांटने के लिए कोई नया कमिशन बनाने के लिए तैयार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने एक सवाल किया एकानमिक वायबिलिटी के बारे में। मेरे पास आँकड़े हैं, अगर वह चाहें तो वह मैं उन को दे सकता हूँ। हिमाचल के 1970-71 के बजट एस्टिमेंटस में रेवेन्यू रिसीटस हैं 20 करोड़ के करीब, नान-प्लेन्ड एक्स्पेन्डिचर 40 लाख के करीब, रेवेन्यु गैप 20 करोड़ के करीब । मणिपुर में नान-प्लेन्ड रेवेन्यु गैप 10 करोड़ के करीब, त्रिपुरा में 14 करोड़ के करीब ।

श्री बलराज मधोक : नागालैंड का बतलाइये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नागालैंड के फिगर्स नहीं हैं । मेरे पास इस समय यूनियन टेरिटरीज के ही फिगर्स हैं ।

दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने किया कि क्या चार पांच राज्यों में देश का विभाजन किया जायेगा ? तो उस का उत्तर मैं दे चुका हूं ।

श्री राम गोपाल शालवाले : मैंने प्रधान मंत्री जी की बात कही है । परसों दिल्ली के डेपुटेशन से उन्होंने कहा था कि वह देश के टुकड़े नहीं करना चाहती । अगर दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जायेगा तो देश के टुकड़े हो जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि आप ने देश में इतने छोटे छोटे राज्य बना कर देश के टुकड़े क्यों कर दिये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : टुकड़े बनाने का कोई सवाल नहीं है । जो समस्यायें इन जगहों में थीं उन से माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं और किन कारणों से राज्य बनाये गये । उन से भी वह भली भांति परिचित हैं ।

Export of Surgical Instruments to U. S. S. R.

*606. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether India will export surgical instruments to the Soviet Union during the next four months ;

(b) whether an agreement to this effect has been signed between the two countries ; and

(c) if so, the terms of the agreement ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A contract has been signed between the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., New Delhi and MEDEXPORT, Moscow for the supply of instruments worth Rs. 23.96 lakhs to USSR from India during the period January to April, 1971.

श्री यशपाल सिंह : यह ऐग्रीमेंट किस बेसिस पर हुआ है ? बार्टर बेसिस पर हुआ है या रुपी पेमेंट बेसिस पर हुआ है, किसी एक्स्चेंज बेसिस पर हुआ है या गुडबिल के नाम पर हुआ है ?

श्री ल० न० मिश्र : रूस के साथ हमारा रुपी ट्रेड रहता है । हमारे बीच एक बाइलेटरल ट्रेड पैक्ट है और यह भी रुपी पेमेंट है और यह भी रुपी पेमेंट बेसिस पर है ।

श्री यशपाल सिंह : यह ऐग्रीमेंट सिर्फ अप्रैल तक के लिये ही क्यों हुआ, साल भर के लिये क्यों नहीं हुआ । आम तौर से सारे ऐग्रीमेंट साल भर के लिए हुआ करते हैं तब फिर यह चार महीने के लिए क्यों हुआ ?

श्री ल० ना० मिश्र : बात यह थी कि रूस के साथ जो हमारा व्यापार समझौता था उस की अवधि समाप्त हो रही थी और हम को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटस वगैरह की जरूरत थी । इस लिये यह समझौता किया गया है । जब नया समझौता होगा तब वह इस की जगह ले लेगा ।

Import from U. S. S. R.

*607. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether India's imports from the U. S. S. R. in 1969-70 amounted to about Rs. 170.40 crores and out of this about Rs. 53.70 crores came under the category of 'special transactions not classified according to kind, not elsewhere specified; and

(b) if so, the details of the items included in the said category ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Yes, Sir.

(b) Imports which cannot be classified into any of the existing categories provided for under the Revised Indian Trade Classification are clubbed together under the general nomenclatuae of "special transactions". Consequently, details in regard to such items are not available with statistical authorities.

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Sir, I urge you to consider that here is a large amount of imports and there is a deliberate attempt to deny information to the House and I will show you how. If that is so, how can anyone ask any supplementary ?

These are the Government's own statements of monthly statistics of foreign trade where there are ten different categories including foods, raw materials, fuel, chemicals, manufactures, machinery equipment and miscallancous, where even items of Rs. 1½ crores are also shown. But there is a special transaction, which he does not want to disclose, of Rs. 53 crores which has been imported only for the first time this year. It is not imported last year. So, I would ask the Minister, when he is prepared to give details of Rs. 1½ crores, why it is that details of an amount of Rs. 53 crores only from the USSR as import under special transaction are not disclosed and what are the items.

SHRI LOBO PRABHU : How much is for election ?